पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रंजीत कुमार एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 138

10 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या हत्या के अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने का विवादित निर्णय टिकने योग्य है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता---धारा 302, 34---हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---चोटों की संख्या, उद्देश्य, घटना का समय और स्थान साबित करने में विफलता---अपराध की प्रथम सूचना को दबाने का प्रभाव।

निर्णय: प्रत्येक अपराध में जो किसी विशेष चिन्हित स्थान पर किया जाता है, घटना के स्थान को साबित करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे घटना के स्थान को साबित करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक मानी जा सकती है और वर्तमान मामले में भी यही स्थिति है क्योंकि अभियोजन पक्ष कथित घटना के स्थान को स्थापित करने में विफल रहा है जिसका वर्णन अभियोजन पक्ष की कहानी में किया गया है --- वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से, मृतक की हत्या करने के लिए अपीलकर्ताओं की ओर से कोई मजबूत मकसद प्रकट नहीं होता है और उक्त

परिस्थिति भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में जाती है --- अपीलकर्ता संजीत कुमार द्वारा कथित रूप से हसुआ से किए गए वारों की संख्या के संबंध में गंभीर विरोधाभास है और यह अभियोजन पक्ष की कहानी में भी गंभीर संदेह पैदा करता है --- अभियोजन पक्ष की कहानी में बताए गए पीड़ित की मृत्यु के समय और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा बताए गए मृत्यु के समय के संबंध में गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी में भी गंभीर संदेह पैदा करता है हमलावर/अपीलकर्ता, जिसने पीड़ित पर हमला करने में उस हसुआ का प्रयोग किया था, को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था तथा जांच में उक्त त्रुटि अभियोजन पक्ष की कहानी पर भी गंभीर दाग लगाती है --- किसी अपराध से संबंधित प्रत्येक आपराधिक मामले में, ऐसे अपराध के घटित होने के संबंध में प्रथम सूचना को दबाना अभियोजन पक्ष के मामले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है तथा यदि यह स्थापित हो जाता है कि वास्तविक प्राथमिकी को दबा दिया गया था, तो इससे अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज किया जा सकता है --- विरोधाभास तथा वैशाली थाने के एसएचओ द्वारा प्राप्त घटना की प्रथम सूचना से संबंधित सनहा को प्रस्तुत न करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घटना की वास्तविक प्रथम सूचना को पुलिस द्वारा जानबूझ कर दबा दिया गया था, जो अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है --- जांच रिपोर्ट को भी अभियोजन पक्ष द्वारा दबा दिया गया था, क्योंकि उसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत एवं प्रदर्शित नहीं किया गया था --- दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया --- अपील स्वीकृत की गई। (पैरा- 14-20)

न्याय दृष्टान्त

सैयद इब्राहिम बनाम ए.पी. राज्य, (2006) 10 एस.सी.सी. 601; रामसेवक एवं अन्य बनाम एम.पी. राज्य, (2004) 11 एस.सी.सी. 259; नंद लाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2023) 10 एस.सी.सी. 470; .....पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता---धारा 302, 34---दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 161, 374

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---हत्या---प्रत्यक्षदर्शी गवाह---घटना का समय और स्थान---घटना का उद्देश्य----अपराध की प्रथम सूचना---अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में विरोधाभास---संदेह का लाभ।

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र परीक्षण संख्या 455/2014 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-III, वैशाली, हाजीपुर की अदालत द्वारा दिनांक 29.11.2016 को दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिनांक 02.12.2016 को सजा का पारित आदेश

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से : श्री आकाशदीप, अधिवक्ता; श्री श्यामेश्वर कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री उपेन्द्र योगेश, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

सूचनाकर्ता की ओर से : श्री लक्ष्मीन्द्र कुमार यादव, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.138

थाना मामला संख्या-179 वर्ष-2014 थाना-वैशाली जिला-वैशाली से उत्पन्न

==========

1. रंजीत कुमार

2. संजीत कुमार, दोनों पुत्र- प्रदीप राय, दोनों निवासी - गाँव-रघुनाथपट्टी, थाना- वैशाली, जिला-वैशाली

... .याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थि/यों के लिए	:	श्री आकाशदीप, अधिवक्ता
		श्री श्यामेश्वर कुमार सिंह, अधिवक्ता
		श्री उपेंद्र योगेश, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री अभिमन्यु शर्मा, अधिवक्ता
सूचक के लिए	:	श्री लक्ष्मींद्र के. यादव, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

दिनांक : 10-04-2025

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आकाशदीप, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी श्री अभिमन्यु शर्मा और सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री लक्ष्मींद्र कुमार यादव को सुना।

2. वर्तमान आपराधिक अपील, वैशाली थाना मामला संख्या 179/2014 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 455/2014 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-III, वैशाली, हाजीपुर की न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.11.2016 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 02.12.2016 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आई.पी.सी.') की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अपीलकर्ताओं पर 5,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न करने पर दोषियों/अपीलकर्ताओं को दो महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है।

<u>अभियोजन की कहानीः-</u>

3. एफआईआर से अभियोजन पक्ष की कहानी का सार इस प्रकार है:--

सूचक अनिल कुमार (पीड़ित का पुत्र) के अनुसार दिनांक 17.07.2014 को लगभग 5:00 बजे, उसकी मां लीला देवी (मृतका, जिसे इसके बाद पीड़िता कहा जाएगा) अपने खेत की देखभाल के लिए चौर क्षेत्र में जा रही थी ('चौर' शब्द का अर्थ गांव के बाहर स्थित एक स्थान है), जब वह चौर क्षेत्र में पहुंची, तो उसने देखा कि आरोपी/दोषी अर्थात् रंजीत कुमार और संजीत कुमार एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, तब उसकी मां (पीड़ित) ने उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तब आरोपी रंजीत कुमार ने कहा कि उसके घर में होने वाले सभी घरेलू झगड़ों के लिए मुख्य रूप से पीड़िता ही जिम्मेदार है, और उसे मार दिया जाना चाहिए और उसके बाद, दोषी/अपीलकर्ता रंजीत कुमार ने पीड़िता के कंधे को पकड़ लिया और फिर अपीलकर्ता संजीत कुमार ने पीड़िता के पेट में हसुआ (दरांती) से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप

उसकी मौके पर ही मौत हो गई, उसके बाद, दोनों आरोपियों ने दरांती लेकर भागने की कोशिश की लेकिन अपीलकर्ता संजीत कुमार को पीछा कर रहे लोगों ने पकड़ लिया और अपीलकर्ता रंजीत कुमार भागने में सफल रहा।

4. उपरोक्त अभियोजन कहानी का वर्णन करते हुए, सूचक अनिल कुमार, (पी.डब्लू.-7 के रूप में परीक्षित) ने वैशाली पुलिस स्टेशन में एक लिखित आवेदन (प्रदर्श-1) दायर किया, जिस पर दो व्यक्तियों, अर्थात्, उमेश कुमार और अरविंद कुमार ने एफआईआर दर्ज करने के तथ्य के गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर किया और उस आधार पर, वैशाली थाना मामला संख्या 179/2014 दिनांक 17.07.2014 को आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत हत्या के अपराध के लिए औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई, जिसने आपराधिक कानून को गति दी और जांच शुरू की गई।

5. जाँच पूरा होने के बाद, पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए दोनों अपीलार्थियों/दोषियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसी अपराध का संज्ञान लिया जिसके लिए दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था और उसके बाद उनके मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

6. दोनों अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के तहत आरोप लगाए गए। आरोप को पढ़कर सुनाया गया और उन्हें हिंदी में समझाया गया, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और आरोप के तहत मुकदमा चलाने का दावा किया।

7. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस गवाहों को पेश किया और उनसे पूछताछ कीः-

	नाम	अभियोजन के अनुसार प्रकृति	प्रासंगिकता
पी.डब्लू.-1	सकीला देवी	प्रत्यक्षदर्शी	मृतक की गोतनी
पी.डब्लू.-2	रीता देवी	प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करना	मृतक की बेटी
पी.डब्लू.-3	बासुदेव राय	सुनी सुनाई गवाही	मृतक का पति
पी.डब्लू.-4	सुनील कुमार	प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करना	मृतक का बेटा
पी.डब्लू.-5	उमेश कुमार	सुनी सुनाई गवाही	सूचना देने वाले का रिश्तेदार
पी.डब्लू.-6	दारोगा राय	मौका गवाह होने का दावा करना	सूचना देने वाले का दोस्त
पी.डब्लू.-7	अनिल कुमार	सूचना देने वाला	मृतक का बेटा
पी.डब्लू.-8	मो. रफीक	जाँच अधिकारी	मामले की जांच की
पी.डब्लू.-9	डॉ. अनिल कुमार	चिकित्सा अधिकारी	पी. एम. आर. के पर्यवेक्षक
पी.डब्लू.-10	डॉ. नवीन कुमार	चिकित्सा अधिकारी	पोस्टमार्टम करवाया।

दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रमाणित किया और उन्हें प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जो निम्नानुसार हैं: -

प्रदर्श 1.	लिखित आवेदन पर उमेश राय के हस्ताक्षर
प्रदर्श 1/1	सूचक द्वारा दायर लिखित आवेदन
प्रदर्श 1/2	लिखित आवेदन पर अनुमोदन

प्रदर्श 2	औपचारिक एफआईआर पर मोहम्मद रफीक (आई.ओ.) के हस्ताक्षर
प्रदर्श 3	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर अनिल कुमार (पी.डब्लू.-9) के हस्ताक्षर
प्रदर्श 3/1	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

8. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे होने के बाद, अपीलकर्ताओं के बयानों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') की धारा 313 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया, जिससे उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ दिखाई देने वाली मुख्य परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर मिला, जिसमें अपीलकर्ताओं ने खुद को निर्दोष होने का दावा किया, जबकि उनके खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और उन्होंने कोई विशेष बचाव नहीं किया।

9. अपीलार्थियों ने अपने बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।

10. अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते समय, विद्वत विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पी.डब्लू. संख्या-1, 2, 4 और 6 की गवाही पर भरोसा किया और उन्हें हत्या की कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी माना और साथ ही पी.डब्लू. संख्या-3, 5 और 7 पर भी भरोसा किया, हालांकि उन्हें सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह माना गया, लेकिन उनके साक्ष्य को अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के रूप में माना गया। हमले के तरीके, घटना के समय और मृतक के शरीर के जिस हिस्से पर चोट पहुंचाई गई थी, उसके संबंध में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई चिकित्सा राय को भी विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में माना। विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के बचाव पर विश्वास नहीं किया कि उन्हें कथित हत्या में अभियोजन

पक्ष द्वारा झूठा फंसाया गया था, क्योंकि उनके बीच जमीन का विवाद चल रहा था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दुश्मनी दोनों पक्षों को काटती है। पी.डब्लू. संख्या 1, 2, 4 और 5 के साक्ष्य को विचारण न्यायालय ने विश्वसनीय माना, जबकि ये गवाह मृतक के रिश्तेदार थे। इन गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य को विश्वसनीय माना और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से हत्या के आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँः-

11. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आकाशदीप ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, वास्तव में कथित हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से पूरी तरह से स्पष्ट होगा, जिन्होंने खुद को कथित हत्या के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है। अभियोजन पक्ष घटना के स्थान को स्थापित करने में विफल रहा, जिसका विवरण एफआईआर में दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर के अनुसार, कथित घटना 17.07.2014 को लगभग 5:00 बजे हुई थी, लेकिन मृत्यु के समय के बारे में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा दी गई चिकित्सा राय के मद्देनजर, पीड़ित की मृत्यु शाम 5:00 बजे से बहुत पहले हो गई थी। इसके अलावा, संबंधित डॉक्टर द्वारा मृतक (पीड़िता) के शरीर पर पाई गई बाहरी चोट के विवरण, जिसने पोस्टमार्टम किया था, और गवाहों के अनुसार पीड़िता को लगी चोटों के विवरण, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने आरोपी/अपीलकर्ताओं द्वारा पीड़िता के शरीर पर हमले होते देखे थे, के बीच गंभीर विरोधाभास है। कथित घटना के तुरंत बाद पीड़िता को घटनास्थल से उसके घर लाने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगति है। जांच अधिकारी उस सनहा को प्रस्तुत करने में विफल रहा,

जिसे कथित घटना की पहली सूचना मिलने पर उसके द्वारा दर्ज किया गया था, इसलिए, वास्तविक पहली सूचना को पुलिस द्वारा दुर्भावना से जानबूझकर दबा दिया गया था, जो पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता है और अभियोजन पक्ष के मामले को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है। यह भी कहा गया है कि जिन महत्वपूर्ण गवाहों पर ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते समय भरोसा किया था, वे मृतक के रिश्तेदार हैं, इसलिए वे अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में पूरी तरह से रुचि रखते थे और अभियोजन पक्ष स्वतंत्र व्यक्तियों को गवाह के रूप में पेश करने में विफल रहा, इस तथ्य के बावजूद कि घटनास्थल के पास कुछ ग्रामीण काम कर रहे थे और इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य प्रासंगिक है। अंत में यह भी कहा गया है कि हथियार के रूप में इस्तेमाल किए गए कथित उपकरण को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया था, जबकि अपीलकर्ता संजीत कुमार को अभियोजन पक्ष के अनुसार घटनास्थल पर पकड़ा गया था और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और इसके अलावा जांच अधिकारी द्वारा कथित हथियार को बरामद करने और जब्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा दी गई बाहरी चोट का विवरण मृतक के गर्दन के क्षेत्र में चोट पहुंचाने के आरोप की पुष्टि नहीं करता है जैसा कि अभियोजन पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा बताया गया है। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से पीड़ित को मारने के लिए मजबूत मकसद को स्थापित करने में भी विफल रहा।

<u>विद्वान एपीपी और सूचक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ:--</u>

12. दूसरी ओर, सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी ने तर्क दिया है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले पी.डब्लू.-10 द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य से पीड़ित के पेट पर दरांती से

हमला करने के आरोप की पूरी तरह पुष्टि होती है। अपीलकर्ता संजीत कुमार को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था और पी.डब्लू. संख्या 1, 2, 4 और 6 की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है और अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा घटनास्थल और पीड़िता के शरीर के अंगों के संबंध में उनकी गवाही में बताए गए विरोधाभास, जहां दरांती से वार किए गए थे, मामूली प्रकृति के हैं और एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी, जो इसे विश्वसनीय बनाती है और सूचक ने एफआईआर साबित कर दी है और कथित घटना के होने को साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या में गवाह हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी पीड़िता की हत्या के लिए अपीलकर्ताओं की ओर से मकसद का वर्णन और साबित किया है क्योंकि वे पीड़िता को एक डायन मानते थे और उसे अपनी सभी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानते थे, इसलिए आरोपित अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं की सजा उचित है और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

साक्ष्यों पर विचार और विश्लेषणः-

13. हमने दोनों पक्षों को सुना है, विवादित फैसले का अध्ययन किया है और अपीलार्थियों के मुकदमे के दौरान निचली न्यायालय द्वारा लिए गए सबूतों का अध्ययन किया है।

14. अभियोजन पक्ष ने गवाह पी.डब्लू. संख्या 1, 2, 4 और 6 को कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया जबकि अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से यह बचाव किया है कि ये गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं और वास्तव में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने कथित घटना को घटित होते नहीं देखा। अभियोजन पक्ष की इस दलील और

अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए बचाव के आलोक में, हम उक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की सराहना करने जा रहे हैं।

एफआईआर मृतक के पुत्र पी.डब्लू.-7 अनिल कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी। यदि हम एफआईआर की पूरी सामग्री को ध्यान में रखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पी.डब्लू.-7 ने खुद को कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था। लेकिन पी.डब्लू.-1 सकीला देवी, जिन्होंने खुद को घटना की प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था, ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि मृतक उसके ठीक आगे खेत जा रहा था और फिर उसने अपीलकर्ता संजीत कुमार को मृतक पर *हसुआ* से हमला करते देखा और पीड़ित के पेट में *हसुआ* से वार किया और उसी हथियार से मृतक की गर्दन पर भी हमला किया और फिर उसने हमलावर संजीत कुमार को पकड़ लिया। गवाह ने घटना के समय घटनास्थल पर सूचक की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। पी.डब्लू.-2, पीड़िता की पुत्री रीता देवी ने भी कथित हत्या की घटना को स्वयं देखने का दावा किया है तथा उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि कथित घटना के दिन व समय पर वह अपनी मां (पीड़िता) के साथ मक्का की फसल काटने व घास काटने के लिए चौर की ओर जा रही थी तथा उस समय उसकी मां उससे 50 *लगगी* आगे थी (1 *लगगी* = 2743.2 मि.मी. या 3 गज) लेकिन इस साक्षी ने उस समय घटनास्थल पर सूचक की उपस्थिति का खुलासा नहीं किया। लेकिन इस साक्षी (पी.डब्लू.-2) की उपस्थिति के संबंध में पी.डब्लू.-1 ने कुछ नहीं कहा। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा के पैरा संख्या 3 में कहा है कि जब मृतका का शव उसके घर के दरवाजे पर लाया गया तो शोरगुल सुनकर कई व्यक्ति वहां पहुंचे तथा सकीला देवी (पी.डब्लू.-1) और जगदीश राय भी उसी समय वहां पहुंचे। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ संख्या 4 में आगे कहा कि उसका भाई सुनील कुमार (सूचनाकर्ता) जंगबहादुर चौक पर किराना दुकान चलाता है, जिसे घटना की जानकारी दी गई तो वह और बासुदेव नामक व्यक्ति आए और फिर

सकीला देवी (पी.डब्लू.-1) ने उन्हें घटना के बारे में बताया। उसने पैराग्राफ संख्या 6 में आगे कहा कि घटना के समय उसके भाई अनिल, सुनील और पिता दुकान पर थे और पी.डब्लू. 1 (सकीला देवी) ने उसे आरोपियों के कृत्यों के बारे में बताया और बताया कि उनमें से किसने पीड़िता को पकड़ा और उसके साथ मारपीट की।

पी.डब्लू.-4, सुनील कुमार, पीड़िता का पुत्र, ने यद्यपि मुख्य परीक्षण में स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था, परन्तु उसकी अपनी बहन पी.डब्लू. संख्या 2 ने उक्त दावे के विपरीत बयान दिया, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है तथा इसके अतिरिक्त, एफआईआर में सूचक ने घटना के समय घटना स्थल पर इस गवाह की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस साक्षी के अनुसार, उसकी चार बहनें हैं और उनके नाम अनीता देवी, सुनीता देवी, रीता देवी और संगीता देवी हैं और सभी विवाहित हैं और अपने-अपने ससुराल में रहती हैं और उसने स्वीकार किया है कि उसकी और उसके भाई की दुकानें सुभाई चौर और जंगबहादुर चौर में स्थित हैं और इस साक्षी की बहन पी.डब्लू.-2 के अनुसार, कथित घटना के समय, उक्त साक्षी (पी.डब्लू. 4) और सूचक अपनी दुकान पर मौजूद थे और अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि जंगबहादुर चौर घटनास्थल के बहुत करीब स्थित है।

पी.डब्लू.-6, दरोगा राय, भी कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया गया है तथा उसे अभियोजन का बहुत महत्वपूर्ण गवाह माना जा सकता है, क्योंकि उसका मृतका एवं उसके परिवार के सदस्यों से कोई संबंध नहीं है, अतः वह एक स्वतंत्र गवाह प्रतीत होता है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 17.07.2014 को लगभग 5:00 बजे शाम को वह भगवानपुर चौर से होकर राम इकबाल राय नामक व्यक्ति से मिलने जा रहा था, इसी दौरान उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को

पकड़े हुए है तथा दूसरा व्यक्ति उक्त महिला के पेट में हसुआ मार रहा है। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि घटना के समय गवाह को अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसे बाद में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ताओं ने हसुआ मार कर सूचक की मां की हत्या कर दी है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में बताया कि वह सेवई बाजार में किराना दुकान चलाता है, जहां सूचक की मोबाइल दुकान है। इस तथ्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब कथित घटना घटी थी, तब सूचक उसे जानता था, लेकिन उसने घटना स्थल पर सूचक की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया तथा उसने प्रतिपरीक्षा में बताया कि चाकू मारने की घटना के बाद वह घटना स्थल से चला गया तथा अपनी दुकान पर चला गया तथा उस समय सूचक से नहीं मिला तथा घटना के बारे में सूचक से कुछ नहीं कहा तथा घटना के बाद वह नियमित रूप से सूचक से मिलता रहा, लेकिन उन्होंने घटना के बारे में बात नहीं की। इस साक्षी का उक्त आचरण अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह साक्षी तथा सूचक एक-दूसरे को जानते थे तथा एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे, लेकिन फिर भी, कथित घटना के संबंध में उनके बीच कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि इस साक्षी ने कथित घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद होने का दावा किया था। इसके अलावा, इस गवाह की उपस्थिति के संबंध में अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों, पी.डब्लू. संख्या 1, 2 और 4 ने कुछ नहीं कहा। इस गवाह की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए, इस गवाह द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए पिछले बयान के आलोक में बचाव पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जांच अधिकारी से प्रतिपरीक्षा की गई थी। जांच अधिकारी (पी.डब्लू.-8) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि उक्त गवाह (पी.डब्लू.-6) ने यह तथ्य नहीं कहा कि कथित दिन और घटना के समय वह भगवानपुर चौर के रास्ते से जा रहा था और रघुनाथपट्टी चौर में उसने आरोपी को पीड़िता पर हमला करते देखा और

जांच अधिकारी के अनुसार, गवाह पी.डब्लू.-6 ने उसके सामने कहा कि घटना के समय वह रघुनाथ राय के घर में था और एक महिला की हत्या का *शोर* सुनकर वह वहां गया था।

तदनुसार, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पी.डब्लू. संख्या 1, 2, 4 और 6 की अपनी स्वयं की गवाही से उपस्थिति के संबंध में गंभीर विरोधाभासों को देखते हुए, वे कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी प्रतीत नहीं होते हैं, हालांकि, पी.डब्लू. 1 (सकीला देवी) की उपस्थिति के संबंध में, पी.डब्लू. 2 ने कहा कि उक्त गवाह कथित स्थान पर घटना के समय मौजूद था, लेकिन पी.डब्लू.-2 उसके प्रत्यक्षदर्शी होने के दावे के संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और इसके अलावा, पी.डब्लू.-1 की उपस्थिति के बारे में, अन्य गवाहों, जिन्होंने खुद को कथित घटना के होने का दावा किया था, ने कुछ नहीं कहा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त गवाह (पी.डब्लू. 1) ने मुख्य परीक्षा में कहा कि दोषी/अपीलकर्ता संजीत कुमार ने पहले पीड़िता के पेट में हसुआ से वार किया और उसके बाद उसी हथियार से पीड़िता की गर्दन पर दूसरा वार किया और प्रतिपरीक्षा में इसके अलावा, वह अपने रुख पर अडिग रही। लेकिन मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गर्दन पर कोई चोट नहीं पाई गई और इसके अलावा, पी.डब्लू. 4, पी.डब्लू. 7 (सूचनाकर्ता) और पी.डब्लू. 6 (दरोगा राय) ने अपीलकर्ता संजीत कुमार द्वारा मृतका की गर्दन पर हसुआ द्वारा दूसरा वार किए जाने के बारे में नहीं कहा। तदनुसार, इन विरोधाभासों को देखते हुए, ये सभी गवाह पी.डब्लू. संख्या 1, 2, 4 और 6 कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं लगते हैं।

15. अब हम घटना स्थल पर आते हैं। एफआईआर के अनुसार, घटना के कथित दिन और समय पर, पीड़िता अपने खेत को देखने के लिए चौर क्षेत्र की ओर जा रही थी और इस दौरान, चौर क्षेत्र में स्थित एक जमीन पर, दोनों अपीलकर्ताओं ने

पीड़िता के साथ कथित घटना को अंजाम दिया और एफआईआर के अनुसार अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि कथित घटना पीड़िता या किसी और के खेत पर हुई थी। जबकि पी.डब्लू.4 (मृतक के बेटे) के अनुसार, कथित घटना उसके खेत पर हुई थी। आई.ओ. ने कथित घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस बिंदु पर, उससे प्रतिपरीक्षा की गई। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया जो निजाम मियां का खाली खेत था और इस गवाह के अनुसार, उस खेत पर कोई मक्का की फसल नहीं थी और सूचनाकर्ता की जमीन उक्त खेत के पास स्थित थी, जिस पर धान की फसल थी। जबकि पी.डब्लू.2, पीड़िता की बेटी के अनुसार, उसकी माँ (मृतक) मक्का तोड़ने और घास काटने जा रही थी और पी.डब्लू.-4 के अनुसार, कथित घटना उक्त खेत पर हुई थी, लेकिन आई.ओ. (पी.डब्लू.8) का साक्ष्य पूरी तरह से उक्त कहानी के खिलाफ है और उसके साक्ष्य के अनुसार, घटनास्थल पर या मृतक की जमीन पर कोई मक्का की फसल नहीं थी, जो घटनास्थल के पास स्थित थी। और इस गवाह के अनुसार, कथित घटना निजाम मियां नामक एक अलग व्यक्ति के खेत पर हुई थी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा संख्या 5 में आगे बताया कि घटनास्थल या आस-पास के खेतों में मक्के की कोई फसल नहीं थी और घटना के दिन ही उसने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया लेकिन उसे घटनास्थल पर खून की एक भी बूंद नहीं मिली और कथित स्थान पर कथित घटना के होने को दर्शाने के लिए कोई सामग्री या सबूत या कोई संकेत भी नहीं मिला जबकि पी.डब्लू. 4 के साक्ष्य के अनुसार, पीड़िता का कुछ खून घटनास्थल पर गिरा था और इस साक्षी के अनुसार, पीड़िता के शरीर से खून सूचना देने वाले के घर के गेट पर भी गिरा था जहां शव को लाकर रखा गया था। उक्त साक्ष्य की पुष्टि आई.ओ. के साक्ष्य से नहीं होती है, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद उक्त स्थानों का निरीक्षण किया था। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सूचक (पी.डब्लू.-7) ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसने कथित

घटनास्थल की भूमि पर पीड़िता का खून नहीं गिरा हुआ देखा था और बाद में उसने कहा कि घटनास्थल पर जहां धान की फसल थी, वहां धान की फसल को कुचला नहीं गया था। ये सभी साक्ष्य अभियोजन पक्ष के इस दावे में गंभीर संदेह पैदा करते हैं कि घटनास्थल पीड़िता का खेत है और हमारा मानना है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष कथित घटनास्थल को स्थापित करने में विफल रहा है जिसका वर्णन अभियोजन पक्ष की कहानी में किया गया है। प्रत्येक अपराध में जो किसी विशेष पहचाने गए स्थान पर किया जाता है, ऐसे स्थान को साबित करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे घटनास्थल को साबित करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक मानी जा सकती है और वर्तमान मामले में भी यही स्थिति है और इस संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ देना चाहेंगे।

सैयद इब्राहिम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में (2006) 10 एससीसी 601 में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब घटनास्थल स्वयं स्थापित नहीं हुआ है, तो अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। हालांकि, इस उद्धृत मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाह पी.डब्लू.-1 ने घटनास्थल के रूप में चार अलग-अलग स्थानों का संकेत दिया और ऐसी स्थिति वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है, लेकिन ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों से हम पाते हैं कि उस स्थान के बारे में गंभीर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सामग्री है जिसे अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार घटनास्थल कहा जाता है और विशेष रूप से, आई.ओ. के साक्ष्य के मद्देनजर। (पी.डब्लू.-8) ने कथित स्थान पर तत्काल दौरा करने के बावजूद कथित स्थान पर घटना का कोई संकेत नहीं पाया और कथित घटनास्थल पर खून का कोई निशान भी नहीं पाया और इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***रामसेवक और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में (2004) 11 एससीसी 259***

में उक्त निर्णय के पैराग्राफ '14' में की गई टिप्पणी प्रासंगिक है और उद्धृत मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कथित घटनास्थल पर संदेह किया क्योंकि उस मामले से संबंधित कथित घटनास्थल पर खून का कोई निशान नहीं पाया गया था। वर्तमान मामले में, आई.ओ. ने स्वीकार किया कि उसे कथित घटनास्थल पर खून का कोई निशान नहीं मिला तथा सूचक ने स्वयं प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसने घटनास्थल की भूमि पर पीड़िता का खून नहीं गिरा हुआ देखा, जबकि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता संजीत कुमार ने पीड़िता के पेट में हसुआ घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उपरोक्त टिप्पणियों वाले उपरोक्त निर्णयों के सुसंगत पैराग्राफों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

(i) ***सैयद इब्राहिम (उपरोक्त)*** के मामले में, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 11:

> *"11. ऊपर बताए गए सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में..... उन्होंने चार अलग-अलग स्थानों को घटना स्थल बताया है। अपनी मुख्य परीक्षा में उन्होंने कहा कि घटना उनके घर में हुई। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि घटना उनकी पत्नी, मृतक की मां के घर पर हुई। यह निर्विवाद स्थिति और वास्तव में पीडब्लू 1 के इस स्वीकारोक्ति को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कि वह और उनकी पत्नी लगभग दो दशक पहले अलग हो गए थे और वह अपनी पत्नी से मिलने-जुलने के लिए तैयार नहीं थे। तब यह सवाल अपने आप उठता है कि तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद वह कथित घटना को अपनी पत्नी के घर में कैसे देख सकते थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने आगे कहा कि घटना उनकी पत्नी के घर के सामने छोटी गली में हुई। यह उस कथन से बिल्कुल अलग है कि घटना घर के अंदर हुई थी, जहां कथित तौर पर वह, मृतक, उसका बेटा, पीडब्लू 2 और बेटियां, पीडब्लू 3 और 6 मौजूद थे। यह गवाह का अंतिम कथन नहीं है। उसने स्वीकार किया*

कि एफआईआर (एक्सटेंशन पी-1) में उसने घटनास्थल मृतक के घर को बताया था। हालांकि एफआईआर अभी तक ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल गवाह की सत्यता को परखने के लिए किया जा सकता है। पीडब्लू 1 ने स्वीकार किया कि एफआईआर में जो कहा गया था, वह सही था। ***जब घटनास्थल ही स्थापित नहीं हुआ है, तो अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार करना उचित नहीं होगा।"***

(ii) **रामसेवक एवं अन्य *(उपरोक्त)*** के मामले में, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 14:-

*"**14.** हालांकि, मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पीडब्लू 1 के साक्ष्य के उक्त भाग में जो कहा गया था, वह जांच रिपोर्ट के संदर्भ में था, न कि एफआईआर के संदर्भ में। हमने मूल की जांच की है जो हिंदी में है और अनुवाद निश्चित रूप से सही है। साक्ष्य के इस भाग को पढ़ने से पता चलता है कि यह गवाह दो रिपोर्टों के बारे में बात कर रहा था। पहली रिपोर्ट जिसका वह उल्लेख करता है, वह जांच के संबंध में होनी चाहिए जिसके बारे में उसका कहना है कि उसे याद नहीं है कि पुलिस ने मौके पर निरीक्षण के बाद उसके हस्ताक्षर लिए थे या नहीं। साक्ष्य का दूसरा भाग निश्चित रूप से उसकी शिकायत का संदर्भ देता है जिसके बारे में उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह मौके पर ही लिखी गई थी। यह मानते हुए भी कि उसके साक्ष्य के इस भाग की व्याख्या के बारे में कुछ संदेह है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने इसे पुनः परीक्षण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया है, संदेह का लाभ बचाव पक्ष को जाना चाहिए जिसने विशेष रूप से यह रुख अपनाया है कि शव बरामद होने के बाद ही एफआईआर अस्तित्व में आई।* ***हमने यह भी देखा कि घटनास्थल के बारे में भी काफी संदेह है। मेडिकल साक्ष्य से हमें पता चला कि मृतक के शरीर पर तीन बड़े घाव थे, जिससे रक्त वाहिकाएँ कट गई थीं और कलाई के पास उसका हाथ कट गया था और शव घटनास्थल पर तब तक पड़ा रहा, जब तक पुलिस नहीं आ गई, जो लगभग 4 से 5 घंटे बाद आई, लेकिन फिर भी जाँच एजेंसी को घटनास्थल पर कोई खून नहीं मिला। बेशक, अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि घटनास्थल पर बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी यह मानना मुश्किल है कि बारिश के बावजूद मिट्टी***

पर खून के निशान भी नहीं पाए जा सकते थे। ऐसी किसी भी सामग्री का अभाव भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है कि घटनास्थल पर घटना नहीं हुई होगी। अभियोजन पक्ष के मामले में इन कमियों की पृष्ठभूमि में, हमें लगता है कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित नहीं किया है, इसलिए विचारण न्यायालय का सभी आरोपियों को बरी करना उचित था। नतीजतन, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का विपरीत दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं था।"

16. अब हम अपीलकर्ताओं द्वारा कथित घटना को अंजाम देने के उद्देश्य पर आते हैं। प्रत्येक अपराध में, अपराधी का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि, हमेशा निर्णायक नहीं होता है, हालांकि, यह महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रदान कर सकता है, जिससे यह स्थापित करने में मदद मिलती है कि किसी आरोपी व्यक्ति ने अपराध क्यों किया होगा, हालांकि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में, अपराध को स्थापित करने के लिए उद्देश्य एक आवश्यक घटक नहीं है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, दोनों अपीलकर्ता एक-दूसरे पर हमला करते हुए पाए गए थे जब उन्हें संबंधित समय पर पीड़िता ने देखा था और फिर पीड़िता ने उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। इस तथ्य से, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पीड़िता के पास उस समय अपीलकर्ताओं के प्रति अच्छी भावनाएँ थीं, अन्यथा, वह दोनों अपीलकर्ताओं के बीच कथित रूप से हो रहे झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करती। यद्यपि, एफआईआर के अनुसार, अपीलकर्ता रंजीत कुमार ने अपने सभी व्यक्तिगत पारिवारिक झगड़ों के लिए पीड़िता को जिम्मेदार माना है और मृतक के पुत्र पी.डब्लू.-4 द्वारा यह बयान दिया गया है कि दोनों अपीलकर्ता पीड़िता को डायन कहकर पुकारते थे, लेकिन उक्त तथ्य विश्वसनीय नहीं लगता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि पीड़िता या उसके परिवार द्वारा पीड़िता को डायन कहने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ अतीत में कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी,

इसलिए वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से मृतक की हत्या करने के लिए अपीलकर्ताओं की ओर से कोई मजबूत मकसद दिखाई नहीं देता है और उक्त परिस्थिति भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में जाती है।

17. अब हम पीड़िता के शरीर के उन अंगों के बारे में विरोधाभासों पर आते हैं, जहां दोषी संजीत कुमार ने हसुआ से वार किया था, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने बताया है। एफआईआर के अनुसार, अपीलकर्ता संजीत कुमार ने पीड़िता के पेट पर ही *हसुआ* से वार किया था और अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि कथित उसी उपकरण से दूसरा वार पीड़िता के शरीर के किसी अन्य हिस्से पर किया गया था। लेकिन पी.डब्लू. संख्या 1 और 2 के साक्ष्य के अनुसार, जिन्होंने खुद को कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया, अपीलकर्ता संजीत कुमार ने पीड़िता के शरीर पर हंसिया से दो वार किए, पहला पेट में और दूसरा गर्दन पर, जो स्पष्ट रूप से एफआईआर में वर्णित अभियोजन पक्ष की कहानी के विपरीत है और साथ ही पी.डब्लू. 4 और पी.डब्लू. 6 के साक्ष्य के अनुसार, जिन्होंने पीड़िता की गर्दन पर हसुआ (हसुआ) से दूसरे वार के बारे में कुछ नहीं कहा और उनके अनुसार, अपीलकर्ता संजीत कुमार द्वारा पीड़िता के पेट में केवल एक हसुआ वार किया गया था और इसके अलावा, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मध्य क्लैविकुलर लाइन में बाएं डायाफ्रामिक क्षेत्र पर केवल एक चीरा हुआ घाव बाहरी चोट के रूप में पाया गया था और रिपोर्ट में पीड़िता के गर्दन क्षेत्र में हसुआ जैसे उपकरण द्वारा कोई बाहरी चोट नहीं दिखाई गई है। इस प्रकार, अपीलकर्ता संजीत कुमार द्वारा कथित तौर पर हसुआ से किए गए वार की संख्या के संबंध में गंभीर विरोधाभास है और यह अभियोजन पक्ष की कहानी में भी गंभीर संदेह पैदा करता है।

18. अब हम कथित घटना के समय पर आते हैं। एफआईआर के अनुसार, कथित घटना 17.07.2014 को लगभग 5:00 बजे शाम को हुई थी, और अभियोजन पक्ष के सभी भौतिक गवाहों, जिन्होंने खुद को घटना को देखने का दावा किया था, ने स्पष्ट रूप से कहा कि कथित घटना कथित स्थान पर लगभग 5:00 बजे शाम को हुई थी और पीड़ित की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए अभियोजन पक्ष के इस रुख के मद्देनजर, पीड़ित की मृत्यु का समय शाम 5 बजे से 5:15 या 5:30 बजे के बीच था। पीड़िता का पोस्टमार्टम उसी दिन रात 9:45 बजे किया गया था। लेकिन मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता की मृत्यु के समय के संबंध में दी गई राय के अनुसार, मृत्यु जांच के समय से 24 घंटे के भीतर हुई थी, जिसका अर्थ है कि पीड़िता की मृत्यु पोस्टमार्टम जांच के समय से कम से कम 12 घंटे पहले हुई थी। डॉक्टर द्वारा प्रतिपरीक्षा में बताए गए तथ्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि पीड़िता की मृत्यु पोस्टमार्टम जांच के समय से 6 घंटे के भीतर हुई होती तो मेडिकल विशेषज्ञ ने मृत्यु के समय को '6 घंटे के भीतर' माना होता और इस बिंदु पर, पी.डब्लू.-10 (डॉ. नवीन कुमार), जिन्होंने पोस्टमार्टम जांच की थी, से भी प्रतिपरीक्षा की गई और उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के छह घंटे के भीतर पोस्टमार्टम किया जाता है तो हम मृत्यु के समय को 'छह घंटे के भीतर' लिखते हैं और इसी तरह, यदि मृत्यु पोस्टमार्टम जांच के 12 घंटे के भीतर होती है, तो हम '12 घंटे के भीतर' लिखते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिए गए चिकित्सीय निष्कर्षों के अनुसार, जब मृतक की जांच की गई तो उसके शरीर के चारों अंगों में कठोरता पाई गई। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, कठोरता मृत्यु के लगभग दो घंटे बाद शुरू होती है और लगभग 8 से 12 घंटे में पूरी हो जाती है और 24 घंटे या उससे अधिक तक रह सकती है। वर्तमान मामले में, शव का पोस्टमार्टम 17.07.2024 को रात 9:45 बजे किया गया था और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, कथित घटना 17.07.2014

को शाम लगभग 5:00 बजे हुई थी, इसलिए, ऐसी स्थिति में, जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था, तब शरीर के चारों अंगों में कठोरता संभव नहीं थी क्योंकि मृतक की मृत्यु और पोस्टमार्टम परीक्षा के बीच केवल लगभग पांच घंटे का अंतर था। इन चिकित्सा रायों से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता की मृत्यु 17.07.2014 को शाम 5:00 बजे से काफी पहले हो गई थी, ऐसे में अभियोजन पक्ष की कहानी में बताई गई पीड़िता की मृत्यु के समय और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा बताई गई मृत्यु के समय के संबंध में गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी में भी गंभीर संदेह पैदा करता है।

19. अब हम प्रथम सूचना रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर आते हैं। किसी अपराध से संबंधित प्रत्येक आपराधिक मामले में, ऐसे अपराध के होने के संबंध में प्रथम सूचना को दबाना अभियोजन पक्ष के मामले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और यदि यह स्थापित हो जाता है कि वास्तविक एफआईआर को दबा दिया गया था, तो इससे अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्तमान मामले में, कथित घटना की प्रथम सूचना जो लिखित आवेदन के रूप में थी, 17.07.2014 को शाम 07:45 बजे दायर की गई थी, लेकिन जांच अधिकारी (पी.डब्लू.-8) के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने एफआईआर दर्ज होने से पहले जांच शुरू कर दी थी और उन्होंने प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ नंबर 3 में कहा कि उन्हें घटना की सूचना शाम 5:20 बजे टेलीफोन पर मिली थी, उसी आधार पर, सनहा नंबर 370 भी दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने केस डायरी में उक्त सनहा का पूरा विवरण नहीं दिया और न ही विचारण न्यायालय में सनहा की प्रति दाखिल की। अतः इस कथन के अनुसार, आई.ओ., जो उस समय संबंधित थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) थे, को दिनांक 17.07.2014 को शाम 5:20 बजे कथित घटना की सूचना मिली थी और उन्होंने उस सूचना को सनहा संख्या 370 के रूप में लिखित रूप में दर्ज भी किया था, लेकिन उसे दबा दिया गया और ट्रायल कोर्ट में पेश

नहीं किया गया तथा उक्त सनहा को कथित घटना की वास्तविक प्रथम सूचना माना जा सकता है, लेकिन पुलिस द्वारा उसे दबा दिया गया। पी.डब्लू.-7 के अनुसार सूचक ने अपनी लिखित सूचना एसएचओ वैशाली को दी। जबकि पी.डब्लू.-8 के अनुसार सूचक द्वारा लिखित आवेदन उन्हें पीड़ित के घर के दरवाजे पर दिया गया। यह विरोधाभास तथा वैशाली थाने के एसएचओ द्वारा प्राप्त घटना की प्रथम सूचना से संबंधित सनहा संख्या 370 प्रस्तुत न करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घटना की वास्तविक प्रथम सूचना को पुलिस द्वारा जानबूझ कर दबा दिया गया था, जो अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है तथा इस संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नंद लाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के मामले में पारित निर्णय **(2023) 10 एससीसी 470** में की गई टिप्पणी का संदर्भ देना चाहेंगे तथा इस निर्णय के सुसंगत पैरा संख्या 28 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> *"28. हम पहले ही आरोपी 11 नरेश कुमार को लगी चोटों के बारे में देख चुके हैं। खोमलाल द्वारा 4-11-2006 को सुबह 3.15 बजे एफआईआर दर्ज कराने से काफी पहले, पुलिस आरोपी 11 नरेश कुमार को मेडिकल जांच के लिए ले गई थी। आरोपी 11 नरेश कुमार को मेडिकल जांच के लिए मेडिकल अधिकारी के पास भेजने वाले मेमो में उल्लेख है कि आरोपी 11 ने पुलिस को सूचित किया था कि रात करीब 8.30 बजे आत्माराम (पीडब्लू 1) ने उस पर हमला किया था। निर्विवाद रूप से, अभियोजन पक्ष ने उक्त घटना के संबंध में जानकारी को दबा दिया है। अभियोजन पक्ष ने आत्माराम (पीडब्लू 1) द्वारा दर्ज एफआईआर को भी दबा दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने का प्रयास किया है। मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अभियुक्त 11 नरेश कुमार द्वारा लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण, हमारा विचार है कि अभियुक्त 11 नरेश कुमार संदेह का लाभ पाने का हकदार है।"*

20. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार अपीलकर्ता संजीत कुमार ने पीड़ित के पेट में एक *हसुआ* (हंसिया) मारा और जब वह भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन एफआईआर में उक्त लोगों के नाम नहीं बताए गए, जबकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में आया है कि घटनास्थल के पास ही कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे और पी.डब्लू.-2 ने भी कहा है कि हमलावर संजीत कुमार को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जांच अधिकारी द्वारा कथित हसुआ (हंसिया) क्यों नहीं जब्त किया गया या बरामद नहीं किया गया, जबकि मुख्य हमलावर/अपीलकर्ता, जिसने पीड़ित पर हमला करने में उस हसुआ का इस्तेमाल किया था, उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया था और जांच में उक्त दोष भी अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर दाग लगाता है। आई.ओ. (पी.डब्लू.-8) ने प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ संख्या 4 में कहा है कि उसने मृतक की जांच रिपोर्ट शाम 6:28 बजे तैयार की थी, जिससे पता चलता है कि यह रिपोर्ट औपचारिक एफआईआर दर्ज होने से पहले ही तैयार कर ली गई थी, क्योंकि एफआईआर 17.07.2014 को शाम 7:45 बजे दर्ज की गई थी और हैरानी की बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने जांच रिपोर्ट को भी दबा दिया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने इसे दस्तावेजी साक्ष्य में पेश नहीं किया था, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

निष्कर्षः-

21. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर चर्चा करने और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को ध्यान में रखने तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उभरे तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम इस सुविचारित राय पर पहुंचे हैं कि यद्यपि इस मामले में अभियोजन पक्ष मृतक (पीड़ित) की अप्राकृतिक

मृत्यु को साबित करने में सफल रहा, जो मध्य क्लैविकुलर लाइन में बाएं उप-डायाफ्रामिक क्षेत्र पर एक चीरा हुआ घाव था, जिससे मृतक के हृदय के बाएं हिस्से में घातक चोट आई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह (पी.डब्लू. 1, पी.डब्लू. 2, पी.डब्लू. 4 और पी.डब्लू. 6), जिन्होंने खुद को कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था, ऊपर चर्चा किए गए कारणों से घटना के प्रत्यक्षदर्शी प्रतीत नहीं होते हैं और अभियोजन पक्ष की कहानी में वर्णित घटना का स्थान और समय अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और प्रारंभिक जानकारी से स्थापित नहीं होता है, जो कि स्वीकारोक्तिपूर्ण थी। संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. को प्राप्त हुई शिकायत अभियोजन पक्ष द्वारा रोक ली गई, जिससे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए अभियोजन पक्ष के आरोप में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में मौजूद महत्वपूर्ण विसंगतियों और विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि दोनों अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं तथा हम निचली न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि करने के लिए राजी नहीं हैं, इसलिए आरोपित अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 2 अर्थात् संजीत कुमार न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता संख्या 1 अर्थात् रंजीत कुमार जमानत पर है, इसलिए उसे और उसके प्रतिभू को जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

22. परिणामस्वरूप, तत्काल आपराधिक अपील को स्वीकार की जाती है।

23. निर्णय की प्रति तत्काल विचारण न्यायालय के साथ-साथ संबंधित जेल प्राधिकरण को भी सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।

24. एलसीआर को तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति) **(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)**

अन्नु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।